



# सांध्य दैनिक

# 4 PM

[www.4pm.co.in](http://www.4pm.co.in) [www.facebook.com/4pmnewsnetwork](https://www.facebook.com/4pmnewsnetwork) [@Editor\\_Sanjay](https://twitter.com/Editor_Sanjay) [YouTube @4pm NEWS NETWORK](https://www.youtube.com/4pm NEWS NETWORK)



पुरस्तके वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं।

-सर्वपल्ली राधाकृष्णन



जिद...सच की

केंद्र सरकार व एलजी ने धर्म का... | 2 | एक देश एक चुनाव, एक सियासी... | 3 | एशियाई हॉकी में भारत ने जापान... | 7 |

## सूर्य का रहस्य जानने निकल पड़ा आदित्य एल-1



11 बजकर  
50 मिनट  
पर भारत का  
पहला सूर्य  
मिशन लॉन्च

5

सालों तक  
लगातार  
भेजेगा  
तस्वीरें

» चार महीने में पूरा करेगा 15 लाख किमी की दूरी

□ □ □ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

बैंगलुरु। इसरो ने ऊर्जा के सबसे बड़े स्त्रोत सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आज 11 बजकर 50 मिनट पर अपना पहला सूर्य मिशन लॉन्च कर दिया है।

वैज्ञानिकों के मुताबिक यान अगले पांच सालों तक रोजाना 1440 तस्वीरें भेजेगा जिसकी मदद से सूर्य के अध्ययन में आसानी होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक पहली तस्वीर फरवरी महीने में सामने आ जाएगी। पहला सूर्य मिशन आंतरिक प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन रेसर्च सेंटर से लॉन्च किया है।

चंद्र विजय करने के बाद से चांद की कई खबरें तस्वीरें चंद्र सेकंड में ही हमारे

मिशन में 400 करोड़ रुपये हुए खर्च

इसरो के इस मिशन में घटनान-3 मिशन से भी कम खर्च आया है। इस सौर मिशन में 400 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जबकि ताजा की ओर से लॉन्च दिए गए सौर मिशन में लगभग 12, 300 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।

पास आने लगी थी, ऐसे ही लोगों को इंतजार है कि वो पास से सूर्य की तस्वीरें ले सकें। गौरतलब है कि आदित्य एल-1 का पहला पेलोड विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ (वीईएलसी) लक्षित ऑर्बिट में पहुंचकर रोजाना एक हजार से अधिक तस्वीरें भेजेगा, जो अध्ययन में मददार साबित होंगे। इस खबर में हम आपको बताएंगे आखिर सूर्य की सबसे करीब से ली गई तस्वीर कब सामने आएगी। दरअसल, इस मिशन से सूर्ज की बाहरी

## इंडिया बोला- 24 में देश से उखाड़ फेंकेंगे मोदी सरकार

- » मुंबई में दो दिनी गठबंधन की बैठक संपन्न
- » दिग्गजों की सहमति- लोस चुनाव मिलकर लड़ेंगे
- » सभी बोले- मोदी सरकार सबसे भ्रष्ट और अहंकारी
- » पूरे देश में की जाएंगी रैलियां
- » बीजेपी सरकार की उलटी गिनती शुरू

□ □ □ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

मुंबई। दो दिनों तक मुंबई में चली विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्वेस्टिगेशन अलायंस (इंडिया)' की बैठक मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ खत्म हो गई। इस बैठक में फैसला लिया कि वे अगला लोकसभा जहां तक संभव होगा मिलकर लड़ेंगे तथा सीटों के तालमेल पर तत्काल काम शुरू किया जाएगा।

गठबंधन की बैठक में पारित प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि सीट बंटवारे का काम 'इस हाथ दे, उस हाथ ले' की सहयोगात्मक भावना के साथ जल्द से



आरएसएस, भाजपा व मोदी डे हुए हैं : यहल

कांग्रेस के दो सहयोगी दलों, शिवसेना और दाटूपांडी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने पिछले एक साल में राज्य में विभाजन देखा और उनके कुछ विपरीतों ने भाजपा के साथ हाथ निला लिया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि महाशास्त्र में भाजपा का सफाया हो जाएगा।

महाशास्त्र में लोकसभा की कुल 48

सीट हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विधायक जगत परिषद ने विधायी गठबंधन 'इंडिया' शास्त्रीय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भजपा) को पराजित कर देगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कानूनिक विधानसभा चुनाव के नतीजे को तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी दोहरायी। कांग्रेस ने कानूनिक में

इस साल ग्राम ने हुए विधानसभा चुनावों में जब दस जीत लासिल कर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया था। गांधी ने दाव किया कि शास्त्रीय स्वतंत्रताकांड (आरएसएस), प्रधानकांडी नरेन्द्र मोदी और भाजपा देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी से "उड़े हुए" हैं।

जल्द पूरा किया जाएगा। प्रस्ताव में कहा गया है, "हम 'इंडिया' के घटक दल आगामी लोकसभा चुनाव जहां तक संभव हो मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। विभिन्न राज्यों में सीट-बंटवारे का

काम तुरंत शुरू होगा और लेन-देन की सहयोगात्मक भावना के साथ जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस बैठक में कई कमेटियां बनाई गईं इसमें सभी दलों के सदस्य शामिल किए गए।

हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं : केजरीवाल

केजरीवाल ने साफ और कहा कि कोई संघर्ष नहीं है। और यह कोई भी किसी पर के लिए नहीं आया है। हम सब यहां टेब्ले के 140 करोड़ लोगों के लिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग अपने आप के भेगाने से भी बड़ा संघर्ष है तो उसका पतल विरिचा होता है। दिल्ली के मुद्राकांडी अधिवेद केजरीवाल ने विधायी गठबंधन इंडिया (भारतीय शास्त्रीय विकासालय) में शास्त्रीय चुनावों पर कानूनिक समाजीय गठबंधन के समान के बीच कोई अंतर्लाली काल ही है, जबकि विधायी गठबंधन में इस तरह की दोनों पार्टी के बीताव कोशियों की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक बात देख रख हूं कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए बड़ी तकरीबनी की गई है।

राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए सशक्त विकल्प प्रदान करेंगे : पवार

इंडिया ने गठबंधन की सर्वोच्च ईकाई के रूप में 14 सदस्यों एक महत्वपूर्ण सहिती गठित की जिसने शहर पारा, ती अर बालू, उमर अब्दुल्ला, अमिषेश बर्जनी, तेजस्वी यादव और ती राजा समेत कई दलों के प्रमुख नेता शामिल हैं। समन्वय समिति भी गठबंधन की सर्वोच्च काई के रूप में काम करेगी। अन्य कई समिति भी बनाई गई है। इनसीपी नेता शहर पारा के काम हम सशक्त विकल्प देंगे।

अगली बैठक दिल्ली में : सुपीया सुले

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शहर पारा गुट) की नेता सुपीया सुले ने मुंबई में तीसरी बैठक के समाप्ति के बाद कहा कि विधायी इंडिया गठबंधन की गठबंधन पार्टी विकासालय के बीच विधायी गठबंधन के समान के बीच बैठक राज्यालयी राजनीति दिल्ली में होगी। उन्होंने कहा, आप (नीतियाकारी) इसे काम आयोजित करना चाहेंगे, हम इसे उन तात्परीयों पर आयोजित करेंगे जिसने (यूटीटी) प्रमुख उद्घाटन करके लोगों के बीच विवाद बढ़ाव दिलाया है। इंडिया गठबंधन की वास्तविकता नहीं की गई है।





# एक देश एक चुनाव, एक सियासी दांव !

## विपक्ष बोला- इंडिया गंदबंधन से घबरा गई मोदी सरकार

- » केंद्र की भाजपा सरकार ने चली चुनावी चाल
- » सरकार की दलील- देश के भविष्य के लिए अच्छा
- » 2024 के लोस चुनाव में बन सकता है मुद्दा

नई दिल्ली। एक देश एक चुनाव का मुद्दा उठाकर केंद्र की भाजपा सरकार ने 24 के लोक सभा चुनाव की अपनी रणनीति जता दी है। उसने इसके लिए समिति का गठन भी कर दिया है। हालांकि उसके इस फैसले पर विवाद ने कड़ा एतराज जताया है। जबकि सरकार कह रही इस फैसले से देश को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा और चुनावी खर्च बचेगा जिससे प्राप्त धन का प्रयोग विकास कार्यों में लगेगा। सियासी जानकारों का मानना है कि भाजपा की ओर से चले गए इस दांव को कोई भी राजनीतिक दल खुलकर खारिज नहीं कर सकता। क्योंकि अलग-अलग होने वाले चुनावों से जनता भी सीधे तौर पर प्रभावित होती है। हालांकि अगर एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया लागू हो गई तो क्षेत्रीय दलों के लिए सियासी तौर पर बड़े संकट का सामना भी करना पड़ सकता है।

एक देश एक चुनाव वह पब्लिक  
 इंट्रेस्ट का मुद्दा है जो सीधे तौर पर जनता  
 को प्रभावित करता आया है। हालांकि,  
 राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि वैसे  
 तो यह फैसला सियासी तौर पर बड़ी  
 चुनौतियां वाला है। क्योंकि  
 इसके लिए क्षेत्रीय संगठन  
 खुलकर समर्थन  
 करने से कठता  
 सकते हैं।  
 इसके पीछे वह  
 तर्क देते हैं कि  
 लोकसभा  
 और  
 विधानसभा के  
 चुनावों के  
 मुद्दे पूरी तरह



से अलग होते हैं। चूंकि क्षेत्रीय दल हमेशा स्थानीय मुद्दे और विधानसभा के लिहाज से चुनावी तैयारी करते हैं। ऐसे में अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो मुद्दों की राजनीति में क्षेत्रीय दल खुद को इतना मजबूत नहीं पाएंगे। इसके अलावा देवेश चतुर्वेदी कहते हैं कि सदन में अगर इस पर प्रस्ताव को लाया जाता है तो यह लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के अलावा इसमें साथ देश के अलग-अलग राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता पड़ेगी। वर्ष 2014 के अपने लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ करवाने की दिशा में काम करने का वादा किया था। वर्ष 1967 तक भारतभर में एक साथ चुनाव कराए जाने का चलन रहा है। और देश में चार बार चुनाव इसी तरह हुए थे। वर्ष 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर देने की वजह से यह चलन खत्म हो गया। लोकसभा भी पहली बार वर्ष 1970 में तय समय से एक साल पहले भंग कर दी गई थी, और उसके बाद 1971 में मध्यावधि चुनाव भी हो गए थे। इस फैसले की

# संविधान में संशोधन की जरूरत

पूरे देश में, यानी केंद्र और राज्यों में, एक ही बार में एक साथ चुनाव कराने की कवायद की तरफ आगे कदम बढ़ाने में काफ़ी ज्यादा वक्त लग सकता है। इसके लिए कम से कम चार संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी, संविधान के जिन अनुच्छेदों में संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी, वे हैं। अनुच्छेद 83 (2) इसमें कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, हालांकि इसे समय से पहले भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 85 (2) (बी), लोकसभा को भंग कर देने से मौजूदा सदन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और नए सदन का गठन आम चुनाव के बाद ही होता है। अनुच्छेद 172 (1) एक राज्य विधानसभा भी पांच साल तक अस्तित्व में रहती है, जब तक कि उसे समय से पहले भंग न कर दिया जाए। अनुच्छेद 174 (2) (बी) - राज्यपाल के पास फैब्रिनेट की सलाह पर विधानसभा को भंग करने की शक्ति होती है, राज्यपाल स्वयंवेक का प्रयोग कर सकते हैं, यदि सलाह ऐसे मुख्यमंत्री से मिले, जिसका बहुमत संदेह में हो। किसी भी संवैधानिक



## क्या है एक देश, एक चुनाव?

बता दें कि इस विशेष सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव, समान नागरिक सहिती और महिलाओं के आरक्षण के मुद्दों पर विधेयक पेश करने की सभावना है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विशेष सत्र को लेकर कहा, अमृत काल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। एक देश एक चुनाव के तहत लोकसभा चुनाव और अलग-अलग राज्यों की विधानसभा चुनावों को एक ही समय पर कराया जाएगा। पहले भी कई दफा इस कानून को लाने पर विचार किया गया है। इस बारे में विधि आयोग से अध्ययन भी किया है। आपको बता दें कि इससे पहले देश में 1951-1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और सभी विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराए गए थे। बता दें कि चुनाव कराने की वित्तीय लागत, बार-बार प्रशासनिक स्थिरता, सुरक्षा बलों की तैनाती में होने वाली परेशानी और राजनीतिक दलों की वित्तीय लागत को देखते

जानकारी होते ही बीजेपी के कई नेताओं ने इसे देश के बेहतर भविष्य के लिए

हुए मौजूदा सरकार एक देश, एक चुनाव की योजना पर विचार कर रही है। इसके तहत सरकार लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराना चाहती है। साल 1951-52 में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए, लेकिन बाद में 1968, 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने और 1970 में लोकसभा को समय से पहले भंग होने से यह साथ चुनाव कराने का चक्र बाधित हो गया। यही वजह है कि अब स्थिति ये हो गई है कि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। ऐसे में सरकार फिर से लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। अब इस दिशा में कमटी का गठन एक बड़ा कदम है।

उठाया जाने वाला सही फैसला बताया है।  
वहीं इस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर

## समिति तैयार करेगी रिपोर्ट

एक देश, एक चुनाव की दिशा में सरकार ने पहला कदम उठा दिया है। दरअसल सरकार ने इसकी संभावनाओं पर विचार के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। कमेटी के सदस्यों पर थोड़ी देर में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने सवाल किया है कि अभी इसकी क्या जरूरत है? पहले महागाई, बोरोजगारी जैसे मुद्दों का निवारण होना चाहिए।

## क्षेत्रीय दलों पर पड़ेगा बड़ा असर

राजनीति के जानकारों का मानना है कि एक देश, एक चुनाव अग्रणी देश में लागू हो जाता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय दलों को होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में आमतौर पर गठताता राष्ट्रीय युद्धों के आधार पर और राष्ट्रीय पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं। ऐसे में अग्रणी लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव होने तो हो सकता है कि क्षेत्रीय दलों को इसका नुकसान झेलना पड़े।

आसान नहीं है फैसला

सरकार ने एक देश, एक चुनाव की संभावनाओं पर  
विचार के लिए कमेटी का गठन कर दिया है।

हालांकि सरकार के लिए भी इस फैसले को लागू करना और इस संबंध में कानून बनाना आसान नहीं होगा। दरअसल एक साथ चुनाव कराने के लिए कई विधानसभाओं के कार्यकाल में मनमाने ढंग से कटौती करनी पड़ेगी। जिसका विरोध होना तय है।

## लाखों ईवीएम की पड़ेगी जरूरत

संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक के पारित हो जाने के बाद उसे भारत के आधे राज्यों द्वारा अपनी-अपनी विधानसभाओं में प्रस्तावों के माध्यम से अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। भले ही लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने के लिए संविधान में संशोधन कर लिया जाए, फिर भी देश को भारी संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह चुनाव आयोजित करने के लिए भारत में 25 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और 25 लाख (गोटर-वेरिफाइड

पेपर ऑडिट ट्रेल) की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि फ़्लिहाल चुनाव आयोग मौजूदा प्रणाली से चुनाव करवाने के लिए ही संघर्ष करता रहता है, क्योंकि उनके पास 12 लाख से कुछ ही ज्यादा इवीएम मौजूद हैं.

केंद्र की दलील है कि लॉ कमीशन ने रिपोर्ट में कहा जा चुका है कि देश में बार-बार चुनाव कराए जाने से सरकारी खजाने के पैसे और संसाधनों की जरूरत से अधिक बर्बादी होती है। संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव



Sanjay Sharma

f editor.sanjaysharma  
t @Editor\_Sanjay

## जिद... सच की

# मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर

इतने महीने बाद भी मणिपुर पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट को दखल करना पड़ा। वहाँ वहाँ की मशहूर खिलाड़ी खिलाड़ी व बॉक्सर को गृहमंत्री को पत्र लिखना पड़ा। ऐसे में सबल उठता है कि सरकारें इतना ढीली-ढाली क्यों बनाए हुई हैं। हालांकि अच्छी खबर ये है कि अब धीरे-धीरे वहाँ पर हिंसा पर काबू पाया जाने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार और मणिपुर राज्य सरकार को मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों को भोजन, दवाएँ और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसी बुनियादी आपूर्ति का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जरिट्स जेबी पारदीवाला की पीठ ने लोगों तक राशन पहुंचने से रोकने वाली नाकाबंदी से निपटने का भी निर्देश दिया और सरकार से ऐसा करने के लिए सभी विकल्प तलाशने का आग्रह किया, जिसमें लोगों के लिए हवा से राशन पहुंचाना भी शामिल है।

मामले के मानवीय पहलुओं से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित न्यायाधीशों की समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पीठ को दो मुद्दों की जानकारी दी, पहला, मणिपुर के मोरेह क्षेत्र में नाकाबंदी की वज से बुनियादी राशन प्राप्त करने में परेशानी और दूसरा, कुछ रात शिविरों में खसरा और चिकनपॉक्स का प्रकोप फैलना। जिसके बाद ये निर्देश पारित किए गए। शुरुआत में सीजेआई ने अरोड़ा से पूछा कि समिति सीधे सरकार तक पहुंचने के बजाय अदालत के सामने क्यों पेश हो रही है। इसके बाद सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता को समिति में नियुक्त नोडल अधिकारियों का औपचारिक नोटिस भेजने का निर्देश दिया ताकि समिति सीधे सरकार तक पहुंच सके। इस समय, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुरुा ने हस्तक्षेप किया और कहा कि जब नाकाबंदी की बात आई तो समिति कुछ नहीं कर सकी। एसजी ने इसमें यह भी कहा कि यह समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वहाँ मणिपुर में जातीय संघर्ष की स्थिति को लेकर बॉक्सिंग स्टार एमसी मेरी कॉम ने चिंता जताते हुए कंट्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। मेरी कॉम ने अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा बल दोनों संघर्षरत समूहों को मणिपुर के कॉम गांव में घुसपैठ से रोके। कॉम समुदाय मणिपुर की एक स्वदेशी जनजाति है और अल्पसंख्यकों में सबसे छोटी जनजाति में से एक है। दोनों प्रतिविहीन समुदायों के बीच बिखरे हुए हैं, और सभी लोग समस्याओं के बीच मांसपेशी हुए हैं... दोनों तरफ से मेरे समुदाय के खिलाफ हमेशा अटकलें और संदेह होते हैं, और सभी लोग समस्याओं के बीच मांसपेशी हुए हैं... कमज़ोर अंतरिक प्रशासन और अल्पसंख्यक जनजातियों के बीच समुदाय के रूप में छोटे आकार के कारण हम अपने अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ करने वाली किसी भी ताकत के खिलाफ छड़े होने में सक्षम नहीं हैं।

2023

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

## पुष्परंजन

चीन दुरभिसंधि करता है, दोस्त किसी को नहीं बनाता। जो उसे दोस्त समझने की भूल करते हैं, सन् 62 की स्थिति का सामना करते हैं। रूसी लोडरशिप उसी रास्ते पर है। संभव है उसे भी जोर का झटका धीरे से लगे। अक्टूबर में चीनी प्रधानमंत्री ली छियांग किर्गिस्तान की यात्रा पर जा रहे हैं। मकसद है चीन-किर्गिस्तान-उज्बेकिस्तान रेल परियोजना पर, चर्चा और उसे आगे बढ़ाना। दशकों से लंबित इस रेल परियोजना को अंजाम देने की बात से मास्को प्रसन्न नहीं है। उसकी वजह है सेंट्रल एशिया में चीनी प्रधानमंडल का विस्तार होना। चीन-किर्गिस्तान-उज्बेकिस्तान समरकंद में शंघाई कापोरेशन आर्गेनाइजेशन (एससीओ) की बैठक में सहमत हुए थे कि इस रेल परियोजना पर आगे बढ़ें। इस साल भारत 'एससीओ' का अध्यक्ष देश था, मगर 4 जुलाई, 2023 को जब आभासी शिखर बैठक हुई, इस विषय को चर्चा से दूर रखा गया। जब समरकंद में इस रेल परियोजना पर निपक्षीय सहमति हुई, कूटनीतिक क्षेत्रों में यह कहा गया कि इससे यूरोपियाँ व्यापार को न सिर्फ नया आकार मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय-आर्थिक व भू-राजनीतिक प्रभाव भी पैदा होंगे।

मास्को को लंबे समय से चिंता थी कि यह परियोजना सेंट्रल एशिया में शक्ति के मौजूदा सुरुलन को बिगाड़ सकती है। क्रेमलिन के रणनीतिकार मानते हैं कि बढ़ते चीनी निवेश के कारण यह क्षेत्र चीन पर अधिक निर्भर हो जाएगा। रूस के ट्रांस-साइबेरियन रेलवे ने चीन द्वारा प्रस्तावित रेल परियोजना को सीधी प्रतिस्पर्धा माना है। रूस को चीन-यूरोप रेलवे एक्सप्रेस से भी आर्थिक लाभ मिलता रहा है, जो यूरोप पहुंचने के लिए रूस से होकर

## मध्य एशिया में चीनी रेल से रूस नाखुश

गुजरती है। हाल के वर्षों में किर्गिस्तान ने भी चीनी रेल परियोजना को पुनर्जीवित करने में बहुत दिलचस्पी दिखाई थी। वर्ष 2020 में, तत्कालीन किर्जिं राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव ने देश के लिए रेल नेटवर्क के महत्व पर जोर दिया था, जिसमें चीन-किर्गिस्तान-उज्बेकिस्तान रेलवे रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण था। किर्गिस्तान ने शी प्लस वन के फार्मूले पर भी जोर दिया था, जिसमें रूसी सहकार को जगह देने की जुगत थी। मगर, चीन ने धीरे से इस प्रस्ताव को एक तरफ कर दिया।

सन् 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद, जमीन से धीरे मध्य एशियाई देशों को एक रेलवे नेटवर्क विरासत में मिला जो मॉस्को के बरास्ते रेश विश्व को जोड़ता था। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से पहले, चीन, मध्य एशियाई देशों और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार के लिए रूसी सड़कें वरेलवे प्रमुख धर्मनियों के रूप में कार्य करती थीं। वर्ष 1990 के दशक में प्रस्तावित यह परियोजना तकनीकी, वित्तीय और ट्रैक गेज की चौड़ाई पर असहमति की वजह से खटाई में पड़ गई। किर्गिस्तान दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद से इस चीनी



रेल प्रस्ताव के प्रति गंभीर हुआ। रूस पर प्रतिबंध के बाद सेंट्रल एशिया के कई देश कनेक्टिविटी को लेकर प्रेरणाएँ हो चुके हैं। प्रभावित पक्ष वैकल्पिक मार्गों की तलाश कर रहे हैं, जिनमें से एक चीन-किर्गिस्तान-उज्बेकिस्तान रेलवे है। इस समस्या के हवाले से किर्गिस्तान के राष्ट्रपति बीर्जिं राष्ट्रपति विकास ने 2022 में कहा था, हमारे देश को पानी की तरह इस रेलवे की जरूरत है। रूस ने भी इस परियोजना के मार्ग में बाधक बना नहीं चाहा है।

छह अब डॉलर की इस परियोजना में उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और चीन द्वारा वैकल्पिक मार्ग के रूप में अधिक सूची दियावने के बाद, रूस ने लंबे समय से चले आ रहे अपने रुख को बदल दिया है। बताते हैं कि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति जापारोव ने सितंबर, 2022 में एससीओ सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में उनकी सहमति ले ली थी। उसके बाद से तीनों मुल्कों के शासन प्रमुखों ने इस रेल परियोजना के मासौदे पर हस्ताक्षर किये थे। अब पुतिन की हासी को रूस के कुछ रणनीतिकार सही कदम नहीं

## रणनीति में शामिल हो कुशल पेशेवर और तकनीक

□□□ डॉ. शशांक द्विवेदी

पिछले दिनों केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जी-20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यसमूह के मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया के आपस में जुड़ जाने के बाद साझा सुरक्षा जोखिम पैदा हो गया है। इसके लिए डिजिटल सुरक्षा पर परस्पर तालमेल की सख्त आवश्यकता है। इंटरनेट की बजह से सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज में बदल गई है। साथ ही भारत में जैसे-जैसे डिजिटलीकरण का दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ भी तेजी से बढ़ रही हैं। वर्तमान में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की मांग और आपूर्ति में लगभग 30 प्रतिशत का अंतर दर्ज किया गया है। संकट का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि सिर्फ मई माह में ही 40 हजार पद इस साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में रिक्त पाए गए, जिनके लिए संस्थानों को साइबर सुरक्षा के कुशल पेशेवर नहीं मिल सके।

डेटा की चोरी कर ली। भविष्य में इस तरह के हमलों को रोकने के लिये साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।

फिलहाल यह सवाल उठना बहुत लाजिमी हो गया था कि साइबर हमलों से निपटने के लिए हमारा देश कितना तैयार है? क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामला है जिस पर विचार करना बेहद जरूरी है। हम सब की निर्भरता इंटरनेट पर बहुत ज्यादा बढ़ने की बजह से आज के आधुनिक माहौल में साइबर सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो चली है। साइबर विशेषज्ञों की अनुसार भारत में जितने बड़े सर्वर

मौजूद हैं, वे हैंकिंग प्रुफ नहीं हैं। हमारे यहाँ भी तभी हम जागते हैं, जब कोई बड़ा साइबर अटैक हो। हैकर्स के नए तरीकों का सॉल्यूशन ढूँढ़ने में महीनों लग जाते हैं। एक तरफ हम डिजिटल इंटिड्या और कैशलेस इकॉनॉमी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ डिजिटल प्राइवेसी और डेटा की सुरक्षा के लिए हमारा कानूनी ढांचा बहुत ही प्रारंभिक स्तर का है। हमारा पड़ोसी देश चीन, साइबर सुरक्षा और जासूसी के खतरों को कम करने के लिए खुद के कंप्यूटर चिप और विशाल सर्वर बनाने में जुटा है। लेकिन हम आज भी इसके लिए विदेशी चिप और विशेषज्ञ स्थित रखते हैं। साइबर सुरक्षा के नाम पर कुछ गिनी-चुनी जगहों पर पुलिस का एक महकमा बना दिया गया है, जो अपराधी हो जाने के बाद रस्म अदायगी जैसा कुछ कर देता है। साइबर सुरक्षा की यह अवधारणा ही गलत है। हमें तो विशेषज्ञों का ऐसा सक्षम तंत्र

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, बिग डाटा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी प्रौद्योगिकीयों की बजह से साइबर सुरक्षा के लिए सबको सचेत रहना होगा।

देश के सरकारी रक्षा, विज्ञान और शोध संस्थान और राजनीयिक दूतावास पर साइबर जासूसी का आतंक मंडरा रहा है। जैस



चेयर पोज़

इस आसन को मार्जरी वित्तिलासन कहते हैं। चेयर पोज को उत्कटासन योग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अभ्यास से तनाव, सिरदर्द, कमर दर्द से छुटकारा मिल सकता है। चेयर पोज रीढ़ की हड्डियों और पैरों को मजबूती देता है और शरीर के निचले हिस्से पर असर दिखता है। इसे करने के लिए चेयर पर बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और दोनों दोनों पैरों को फर्श पर रखें। दोनों हथेलियों को पैरों के घुटनों पर रखकर लंबी सांस को भीर की ओर खींचते हुए सीने को बाहर की ओर निकालें। कंधे को पीछे की ओर ले जाएं और धीरे सांस छोड़ें। रीढ़ की हड्डी को पीठ की तरह ले जाकर मोड़ें। इस आसन को कम से कम पांच बार दोहराएं। उत्कटासन योग से कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ का जिक्र मिलता है, हालांकि कुछ रिप्टिशनों में इसे करने की सलाह दी जाती है। जिन लोगों को घुटने का दर्द, गटिया या टखने में मोच की समस्या हो उन्हें इस योग मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। विशेष ध्यान रखें, मासिक धर्म या पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने पर इस योग मुद्रा का अभ्यास करने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें।

## ये योगासन दफ्तर

### में दूर करेंगे

# थकान

शारीरिक सक्रियता कम होने के कारण कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। भले ही लोग प्रतिदिन सुबह सैर पर जाते हैं और पैदल चलकर शरीर को सक्रिय बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन दफ्तर में घंटों बैठकर काम करने से कमर, पीठ और गर्दन में दर्द होने लगती है। दफ्तर का कार्य 8 से 10 घंटे का होता है, इस दौरान कर्मचारी ड्रेस पर लगातार एक ही मुद्रा में बैठकर कार्य करते हैं। कर्मचारी के मन और शरीर दोनों पर ही इसका प्रभाव पड़ता है। शरीर दर्द के साथ ही चर्ची बढ़ने की भी शिकायत होने लगती है। कुर्सी पर बैठकर काम करने से मोटापा बढ़ने लगता है और पेट निकलने लगता है। व्यायाम और योगाभ्यास से शारीरिक परेशानियों और मोटापे को कम किया जा सकता है। हालांकि दैनिक जीवन में अगर आपके पास व्यायाम या योग का वक्त नहीं होता है तो इसे दफ्तर में ही कर सकते हैं। ऐसे योगासन दफ्तर में कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं।

### हंसना नाना है

डॉक्टर ने महिला मरीज से कई सवाल पूछने के बाद जानना चाहा-आपके कितने बच्चे हैं? तनिक लजाते हुए महिला ने बताया-उतने ही है बस जितने रोनाल्डो की जर्सी के नंबर हैं।

गुस्से में लाल-'पीले होते वे महाशय दर्जी की दुकान पर चढ़े और बोले-'देख रहे हो यह सूट? तुम कहते थे, कपड़ा कम है। मटका गली वाले दर्जी ने उसी कपड़े से सूट भी बनाया और जो कपड़ा बचा, उससे अपने पांच साल के लड़के का एक कोट भी बना लिया। मैं तुमसे पूछता हूं..'' मैं खुद ही बताये देता हूं।' दर्जी विनम्रता से बोला, 'असल में मेरा लड़का यारह साल का है।'

पत्नी- शादी से पहले तुम मुझे होटल, सिनेमा, और न जाने कहाँ- कहाँ घुमाते थे, शादी हुई तो घर के बाहर भी नहीं ले जाते.. पति- क्या तुमने कभी किसी को... चुनाव के बाद प्रवार करते देखा है...

गोलू की गर्लफ्रेंड गोलू से- जानू मैं तुम्हारे लिए आग पे चल सकती हूं, नदी में कूद सकती हूं.. गोलू- मैं भी तुमसे बेझिन्हां प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे मिलने अभी आ सकती हो? गर्लफ्रेंड- पागल हो गए हो क्या, इतनी धूप में मैं काली पड़ गई हो...



दफ्तर में कुर्सी पर बैठकर आसानी से स्ट्रेचिंग करके थकान और शरीर में होने वाले दर्द से राहत पा सकते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन और मांसपेशियों में हो रहे दर्द से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इसे करने के लिए कुर्सी पर बैठकर बाहों को ऊपर उठाएं और दोनों हाथों को सिर के ऊपर लाएं। अब दोनों हाथों को सिर के ऊपर ऊपर उठाएं और दोनों हाथों पर जोर दें। सांस को अंदर खींचते हुए हाथों और शरीर के ऊपर भाग को स्ट्रेच करें। तीन से चार बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। प्रतिदिन स्ट्रेचिंग का अभ्यास करने से शरीर में लचीलापन आने लगता है जिससे कि पांव आदि को खोलने, मोड़ने में न तो दर्द होता है और अपने आप ही यह ज्यादा मुड़ने- खुलने लगते हैं, ऐसा होने पर इंसान कठिन से कठिन आसन बढ़ी आसानी से करने लगता है इसलिए पांव की स्ट्रेचिंग का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए।

## ऊर्ध्व हस्तासन

ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर और तान का अर्थ तानना अर्थात् शरीर को ऊपर की ओर तानना ही ऊर्ध्वतानासन है। अनजाने में ही व्यक्ति कभी-कभी आलसवश दोनों हाथ ऊपर करके शरीर तान देता है। शरीर को ऊपर की ओर तानते हुए त्रिव्यं व्यक्ति में स्थिर होना चाहिए। दफ्तर में लगातार काम करने से तनाव हो सकता है, इस आसन के अभ्यास से तनाव कम होता है और रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। गर्दन, कमर और पीठ का दर्द ऊर्ध्व हस्तासन से दूर हो सकता है। इस आसन का अभ्यास करने के लिए कुर्सी पर बिल्कुल सीधी बैठकर सांस को अंदर की ओर खींचे और दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। कुछ देर इसी पोज में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। इस योग को 10 से 15 बार दोहराएं।

### कहानी

### आखिर कर्म ही महान है

एक बार बुद्ध एक गांव में अपने किसान भर्त के यहां गए। शाम को किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन वह भक्त ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी कि कैसा भर्त है कि प्रवचन का आयोजन करके स्वयं गायब हो गया। प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग घर चले गए। रात में किसान घर लौटा। बुद्ध ने पूछा- कहाँ चले गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हें पूछ रहे थे। किसान ने कहा, दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, पर तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैंने घरेलू उपचार करके उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तीव्रियत ज्यादा खराद होने लगी तो मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता तो वह नहीं बचता। आपका प्रवचन तो मैं बात में भी सुन लूंगा। अगले दिन सुबह जब गांव वाले पुनः बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा, यह तो आपका भर्त होने का दिखावा करता है। प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। बुद्ध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और फिर समझाया, उसने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर यह सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा को उसने बिल्कुल ठीक ढंग से समझा है। उसे अब मेरे प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। मैं यहीं तो समझता हूं कि अपने विवेक और बुद्ध से सोचो कि कौन सा काम पहले किया जाना जरूरी है। यदि किसान बीमार बैल को छोड़ कर मेरा प्रवचन सुनने को प्राथमिकता देता तो दवा के बैगर बैल के प्राण निकल जाते। उसके बाद तो मेरा प्रवचन देना ही व्यर्थ हो जाता। मेरे प्रवचन का सार यही है कि सब कुछ त्यागकर प्राणी मात्र की रक्षा करो। इस घटना के माध्यम से गांव वालों ने भी उनके प्रवचन का भाव समझ लिया।

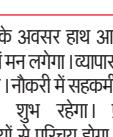
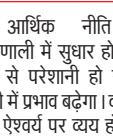
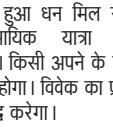
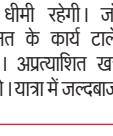
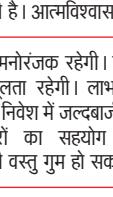
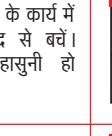
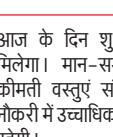
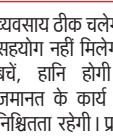
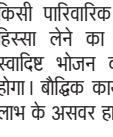
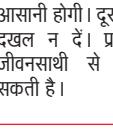
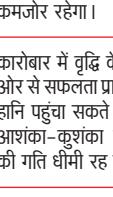
### 7 अंतर खोजें



पंडित संदीप  
आत्रेय शास्त्री

### जानिए कैसा दहेजा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें- 9837081951





# राजस्थान में शासन-व्यवस्था पूरी तरह से नदारद : नड़डा

## बोले-कांग्रेस आलाकमान को खुश करने में व्यस्त हैं सीएम

4पीएम न्यूज नेटवर्क

जयपुर। मणिपुर का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि राजस्थान से एक रुह कंपा देने वाली गरदात सामने आई है। यहां एक आदिवासी महिला को उसके सुसुराल वाले ने सरेआम निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इस गंभीर मामले को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स (पूर्व में टिवटर) पर एक ट्रीट कर राज्य सरकार को धोए।

नड्डा ने मुख्यमंत्री

अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अपना बचा हुआ समय दिल्ली में एक राजवंश को खुश करने में व्यतीत कर रहे हैं। इसके कोई दो राय नहीं है कि राज्य में



राजस्थान सरकार ने तेजी से की कार्रवाई : गहलोत

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट किया था, एकीनी क्राइन को तुरंत अपराध स्थल पर भेजा गया और हमले पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सभ्य समाज में इसके लिए कोई जाहाज नहीं है। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए मामले को फार्स ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा।

सुरक्षा देने में असमर्थ सीएम महिला शक्ति से मार्गे माफी : जोशी

जयपुर। प्रतापगढ़ मामले पर भाजपा प्रेदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि एक बार फिर आज राजस्थान शर्मसार हुआ है। जोशी बोले कि प्रतापगढ़ जिले के धियावाद तहसील के पहाड़ा ग्राम धन्यायत के लियाला कोटा में महिला अत्यावाह की घटना की प्रशासन को भेनक नहीं लगती। ये बताता है कि आखिर राजस्थान वर्षों महिला दुष्कर्म और अत्यावाह में नंबर एक पर है। जिस सरकार के क्षेत्री अपराध को छुपाने के लिए कहते हैं कि परिवार का मामला है। दुष्कर्म होने पर कहते हैं कि ज्ञाते मुकर्जने हैं, मर्दों के प्रेदेश की बात कहते हैं। ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप गृह मंत्री होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। आप इस्तीफा दे और महिला शक्ति से मार्गे माफ़े कि यह सरकार उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए।

महिला सुरक्षा के मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। आए दिन महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न को कोई घटना सामने आती रहती है। राजस्थान के प्रतापगढ़ का वीडियो चौंकाने वाला है। इससे भी बुरी

बात यह है कि राजस्थान में शासन व्यवस्था पूरी तरह से नदारद है। राजस्थान के लोग राज्य सरकार को सबक सिखाएँगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर ढुलमूल रवैये को लेकर राजस्थान सरकार को आडे हाथों लिया। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, आज राजस्थान शर्मसार है। इस बात से पता चलता है कि सरकार को प्रतापगढ़ की इस शर्मनाक घटना की जानकारी तक नहीं हुई।

## अतीक अशरफ जांच आयोग को 1.34 करोड़ देने का विरोध

आजाद अधिकार सेना ने खड़ा किया सवाल

4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अतीक अशरफ हत्याकांड की न्यायिक जांच समिति को दिए गए मानदेय पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल 2023 द्वारा जांच आयोग से संबंधित व्यक्तियों को कुल 1.34 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 30-30 लाख, सभी सदस्यों को 20 लाख और अन्य को 14 लाख शामिल है।

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि जहां



सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को 15 लाख रुपये प्रति वर्ष का पेंशन है, वहीं यहां रिटायर्ड न्यायिक और

अन्य अधिकारियों को अंशकालिक कार्य के लिए कितनी बड़ी धनराशि दिया जाना शासन की मंसा पर गहरी सवाल पैदा करता है। सरकार का यह आचरण पूरी तरह मनमाना है और जनता के पैसे की खुली बर्बादी होने के साथ ही मनचाहा रिपोर्ट प्राप्त करने के दिशा में एक अनुचित प्रयास भी है।

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई हॉकी 5एस वर्ल्ड कप खालिकायर के एक मैच में जापान को बुरी तरह से मसलकर रख दिया। भारतीय टीम ने जापान को 35-1 से रोंदा। इसके अलावा भारत ने एक अन्य मुकाबले में मलेशिया को भी 7-5 से हराया। इस मुकाबले में भारत ने एक के बाद 35 गोल किए। जबकि जापान महज एक ही गोल कर पाया।

मर्दीप मोर की अगुवाई में भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी लीग मैच में गोल की बारिश कर दी। इसके साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में शानदार जगह बना ली है। भारतीय टीम के सामने जापानी टीम पस्त हो गई। टीम ने पहले पांच मिनट के अंदर ही सात गोल कर दिए थे और इसके बाद भी जापानी टीम पर किसी

5एस वर्ल्ड कप खालिकायर में 35-1 से दी मात



तरह का रहम नहीं दिखाया। भारत की तरफ से मनिंदर सिंह 10 गोल दागे। तो मोहम्मद राहिल ने सात, पवन राजभर और गुरजोत सिंह ने पांच-पांच, सुखिंचिंदर ने चार, कसान मनदीप मोर ने तीन और जुगराज सिंह ने एक गोल किया। जापान की तरफ से एकमात्र गोल मसाताका कोबोरी ने किया। भारतीय टीम ने इसके अलावा जापान को 12 अंक लेकर पाकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर रहा जिससे वो सेमीफाइनल के लिए सीधे क्रालिकाई कर गया।

से गुरजोत ने पांच जबकि मनिंदर और राहिल ने एक-एक गोल दागा। मलेशिया की तरफ से आरिक इशाक, कसान इस्माइल अबू मोहम्मद दीन, कमरुलजमान कमरुद्दीन और स्यारमन मत ने गोल किए। दिन की इन दो बड़ी जीत से टीम इंडिया एलीट पूल तालिका में 12 अंक लेकर पाकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर रहा जिससे वो सेमीफाइनल के लिए सीधे क्रालिकाई कर गया।

### बॉडी बिल्डर आदिल अंसारी पीसीएस जे परीक्षा में सफल

लखनऊ। नगर निगम लखनऊ में तैनात हो और गौतमा की शुरुआत करने वाले डॉक्टर अस्पताल असारी के पुत्र आदिल अंसारी ने यूपी पीसीएस जे परीक्षा परीक्षण में 205 वीं ईके के साथ सफलता प्राप्त की। वर्ल्ड ऐपियोल बॉडी बिल्डर की पीसीएस जे में 205वीं ईके परीक्षण में सुवीरी जीता। आदिल याम नगर निगम लखनऊ लोहिया लौयानीवर्सिटी से पीसीएस कर रहे हैं। देवरिया जिले के नवलपुर कर्के के मूल निवासी और शहरी पिकास विभाग में एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद एम ए अंसारी के पुत्र आदिल अंसारी ने बुधवार को आप यूपी पीसीएस जे परीक्षा परीक्षण में 205वीं ईके के साथ सफलता प्राप्त की है। आदिल अंसारी की सफलता पर उनके परीक्षण और शुभेच्छुओं ने बधाई दी।

## भाजपा दंगा-फसाद वाली पार्टी है : तेजस्वी यादव

बोले- लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहती है

4पीएम न्यूज नेटवर्क

पटना। विपक्षी दलों (इंडिया) की तीसरी बैठक से पहले बिहार के डिटी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने भाजपा को दंगा-फसाद वाली पार्टी कह दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग डरे हुए हैं। अगस्त के महीने में ही पिछले साल यानी 2022 में हमलोंगों ने महागढ़बंधन की सरकार बनाई थी। उसी बबत नीतीश जी और लालू जी ने तय किया था कि देश भर के सभी लोगों को एक करेंगे। एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। और, आज देखिए तीक एक बार फिर साल भर बाद मुंबई में बैठक हो रही है।

तेजस्वी ने आगे कहा कि यह विपक्षी दलों की एकता की तीसरी बैठक हो रही है। इसके कई मायने हैं। लोग चाहते थे कि एक सही विकल्प रखा जाए। ऐसा लोग चाहते थे। हमें पूरा विश्वास है कि जो लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते थे। हमें पूरा विश्वास है कि जो लोकतंत्र अध्यक्ष सीपी जोशी ने मनी लॉन्डिंग के इस मामले की जांच सीबीआई की एफआईआर के आधार पर शुरू की थी।

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 538 करोड़ रुपये के मनी लॉन्डिंग (पीएमएलए) केस में जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के संस्थापक नरेश गोयल (74) को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि गोयल को शुक्रवार रात गिरफ्तार किया गया। ईडी गोयल को शनिवार को विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग कर सकती है। ईडी ने मनी लॉन्डिंग के इस मामले की जांच सीबीआई की एफआईआर के आधार पर शुरू की थी।

सीबीआई ने केनरा बैंक धोखाधड़ी मामले में गोयल, उनकी पत्नी अनीता और कंपनी के कुछ पूर्व अधिकारियों को आरोपी बनाया है। सीबीआई ने बैंक की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें बैंक ने आरोप लगाया है कि उसने जेट एयरवेज लिं. (जेएएल) को 848.86 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था जिसमें से 538.62

करोड़ रुपये अब भी बकाया हैं। इस खाते को 29 जुलाई 2021 को फॉर्ड घोषित कर दिया गया था। बैंक का आरोप था कि कंपनी के फोरेंसिक ऑफिस से पता चला कि उसने अपनी अन्य कंपनियों को 1410.41 करोड़ रुपये की मीशन के रूप में भुगतान किया और इस तरह जेट का पैसा बाहर भेजा गया। जेट ने अपनी अनुसंगी कंपनियों को कर्ज या

कर्ज एयरवेज ने साल 2006 में खरस्ताहाल एयर सहारा को 50 करोड़ डॉलर नकद देकर खरीदा था, जो बाद में दूब गई। इससे जेट एयरवेज को बड़ा झटका लगा। जेट एयरवेज स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स को ढूँढ़ने में भी नाकाम रही। इससे कंपनी का घाटा बढ़ता गया। इसी बीच भारतीय विमान बाजार में इंडिया, रूपांश जेट और गोपी एयर जैसी बजट एयरलाइंस की एंट्री हुई, जिन्होंने सर्वे टिकट देकर जेट एयरवेज के मार्केट पर अपना कब्जा कर लिया।</

